खबर संक्षेप

शहडोल में पेंशनरों की आवाज बुलंद

शहडोल। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन (मध्यप्रदेश) शहडोल द्वारा पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने भूपेंद्र सिंह को भी ज्ञापन सौंपकर पेंशनरों की मांगों को शासन स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा शीघ्र निराकरण कराने का आग्रह किया।ज्ञापन में प्रदेशभर के लाखों पेंशनरों की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बढ़ती महंगाई के दौर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन-यापन कठिन होता जा रहा है। ऐसे में शासन को लंबित पेंशन संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान करना चाहिए। संगठन ने सातवें वेतनमान से संबंधित एरियर सहित अन्य देय लाभों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई।
ज्ञापन में पेंशन निर्धारण एवं भुगतान प्रक्रिया में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने, निर्धारित आयु पूर्ण करने वाले पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ स्वतः प्रदान करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप सभी पात्र पेंशनरों को लाभ देने की मांग प्रमुखता से रखी गई। संगठन का कहना है कि वर्षों तक शासकीय सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने वैधानिक अधिकारों के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है।एसोसिएशन ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की अपील की। ज्ञापन के समर्थन में संगठन के जिला पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति भी दर्ज कराई।इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनते हुए पेंशनरों की मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने तथा उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पेंशनरों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगी। संगठन ने कहा कि यदि मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर के पेंशनर लोकतांत्रिक तरीके से आगे की रणनीति बनाने के लिए बाध्य होंगे।

सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

शहडोल। आरसेटी शहडोल में 6 दिवसीय सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षणार्थियों को 'प्रमाण पत्र एवं ड्रेस का वितरण' किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सोलर पैनल की स्थापना, संचालन, रखरखाव, वायरिंग, सुरक्षा एवं सामान्य तकनीकी खराबियों के समाधान के संबंध में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 'प्रशिक्षक अभिषेक जायसवाल' द्वारा प्रतिभागियों को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस से संबंधित तकनीकी जानकारी के साथ-साथ विभिन्न कार्यों का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 'रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं' के बारे में जानकारी दी गई। आरसेटी फैकल्टी श्री दुर्गेश गुप्ता' द्वारा प्रतिभागियों को उद्यमिता विकास, व्यवसाय प्रारंभ करने की प्रक्रिया, विभिन्न 'बैंकिंग योजनाओं एवं ऋण योजनाओं', बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन एवं स्वरोजगार के अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर निदेशक बिप्लव चंद्र, 'ऑफिस असिस्टेंट ज्ञान सागर मांझी' एवं सुश्री अंजली गुप्ता' सहित प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहें।

एसडीएम ने किया पदभार ग्रहण

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने डिप्टी कलेक्टर सुश्री अर्चना मिश्रा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ब्यौहारी नियुक्त किया है। सुश्री मिश्रा ने कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के पद पर पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यालय के अधिकारियो एवं कर्मचारियो से चर्चा कर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

खरला पंचायत में निर्माण के नाम पर खुला डाका

बुढ़ार जनपद में भ्रष्टाचार की ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार

बिना खदान सप्लाई हो गई रेत, फर्जी बिलों से डकारी जा रही लाखों की राशि
सरपंच, सचिव और उपयंत्री की तिकड़ी को मिला जनपद सीईओ का संरक्षण!

शहडोल। जिले की बुढ़ार जनपद पंचायत इन दिनों भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की मंडी बन चुकी है। पंचायतों के विकास के नाम पर शासन से आने वाली लाखों-करोड़ों की विकास निधि पर डाका डालने के लिए सरपंच, सचिव और उपयंत्री (यंत्री) का एक गिरोह सक्रिय है। घाट निर्माण, नाली निर्माण, सीसी सड़क और कल्वर्ट पुलिया जैसे निर्माण कार्यों के नाम पर कागजों में फर्जी बिल लगाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। सबसे हैरतंगेज बात यह है कि इस पूरे फर्जीवाड़े और लूटतंत्र के सिर पर जनपद पंचायत बुढ़ार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी

का वरदहस्त (संरक्षण) प्राप्त है, जिसके चलते शिकायत के बाद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई गाज नहीं गिर रही है।

पंचायतों में हो गई लाखों की रेत सप्लाई

बुढ़ार जनपद की ग्राम पंचायत खरला में जारी भ्रष्टाचार का यह नया कारनामा सामने आया है। वर्तमान में जिले में आधिकारिक रूप से रेत खदानें संचालित नहीं हैं, लेकिन खरला पंचायत के अभिलेखों और बिल-वाउचरों में धड़ल्ले से रेत की सप्लाई दर्ज की जा रही है। घाट, नाली, सीसी रोड और पुलिया निर्माण के नाम पर ऐसी फर्मों के बिल लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम पर कभी धरातल पर सामग्री आई ही नहीं। बिना धरातलीय सत्यापन और गुणवत्ता जांच के उपयंत्री की शह पर पूरा खेल चल रहा है।

याचना और प्रांशू फर्म का खेल

ग्राम पंचायत खरला में फर्जी बिलिंग का बड़ा खेल रचा गया है। खरला पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर याचना हार्डवेयर बस स्टैंड चन्नौड़ी और प्रांशू एंटरप्राइजेस खरला जैसी फर्मों के नाम से लाखों रुपये के बिल लगाए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि यदि इन फर्मों के बिलों, जीएसटी नंबरों और धरातल पर हुए सप्लाई के सामान की निष्पक्ष निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो खरला सरपंच-सचिव ही नहीं, बल्कि कमीशनखोरी में लिप्त उपयंत्री भी सीधे

सलाखों के पीछे नजर आएंगे।

जब से संभाला प्रभार, दोगुना हुआ भ्रष्टाचार!

इस पूरे महाघोटाले की सबसे मुख्य कड़ी बुढ़ार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की संदिग्ध भूमिका है। जब से इन्होंने बुढ़ार जनपद के मुखिया का प्रभार संभाला है, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। जहां ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य की जरा भी आवश्यकता नहीं होती, वहां भी कमीशन के चक्कर में मनमाने तरीके से निर्माण स्वीकृत करा दिए जाते हैं। सीईओ के कार्यकाल में आज तक किसी भी भ्रष्टाचारी सरपंच, सचिव या उपयंत्री पर कोई दंडात्मक कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को संज्ञान में लाने और लिखित शिकायतें सौंपने के बावजूद न तो कोई जांच कमेटी बनाई जाती है और न ही जनपद का अमला धरातल पर जाकर कार्य की उपयोगिता देखता है। बुढ़ार जनपद में विकास के नाम पर सरकारी पैसे की लूट का यह खेल अब जनता के सब्र का बांध तोड़ रहा है। खरला पंचायत में हुए ये निर्माण कार्य केवल बानगी मात्र हैं, यदि बुढ़ार जनपद की सभी पंचायतों के बिल-वाउचरों का ऑडिट कराया जाए, तो करोड़ों का घोटाला उजागर होगा।

ददराटोला में सचिव की दबंगई
12 लाख की सड़क का पैसा डकारा

रिश्तेदारों से ठेकेदारी और मंत्री-अध्यक्ष के नाम की धौंस!

शहडोल। जिले की जनपद पंचायत गोहपारू अंतर्गत ग्राम पंचायत ददराटोला में विकास के नाम पर शासकीय राशि की खुलेआम लूट और ग्राम सचिव की तानाशाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 20 वर्षों से एक ही पंचायत में खूंटा गाडक़र बैठे दबंग पंचायत सचिव मुकेश तिवारी और सरपंच श्रीमती मीरा बाई सिंह पर विकास कार्यों की राशि डकारने, रिश्तेदारों से ठेकेदारी कराने और ग्रामीणों व पंचों को धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। सचिव की इस गुंडागर्दी से परेशान ग्रामीणों ने अब कमिश्नर शहडोल की चौखट पर दस्तक देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दबंग सचिव के तत्काल स्थानांतरण (तबादले) की गुहार लगाई है।

12 लाख की सीसी सडक़ कागज़ों में सिमटी

शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने खुलासा किया है कि ग्राम बहेरा में लक्ष्मण यादव के घर से लेकर अयोध्या सिंह के घर तक लगभग 350 मीटर की सीसी सडक़ निर्माण के लिए 12 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। आरोप है कि सचिव मुकेश तिवारी और सरपंच ने मिलीभगत करके 01 मई 2026 तक 4 लाख 36 हजार रुपये का आहरण (निकासी) कर लिया। लेकिन धरातल पर काम की बात करें तो सडक़ अधूरी और खस्ताहाल पड़ी है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वीकृत शौचालय निर्माण की राशि भी पूरी तरह निकाल ली गई, जबकि निर्माण कार्य का आज तक अता-पता नहीं है।

20 साल से जमाया कब्जा

सचिव मुकेश तिवारी की दबंगई का आलम यह है कि वह पिछले 20 वर्षों से एक ही ग्राम पंचायत में जमा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी प्रशासन द्वारा इसका स्थानांतरण किया जाता है, यह न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) ले आता है। अब तक तीन बार तबादले के बावजूद यह सचिव ददराटोला पंचायत छोडऩे को तैयार नहीं है और खुलेआम अपना एकछत्र राज चला रहा है।

अपात्रों को बांटे प्रधानमंत्री आवास

पंचायत की शासकीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में आने वाले सभी विकास कार्यों का ठेका सचिव अपने निजी रिश्तेदारों को दे देता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों, उपसरपंच और ग्रामीणों को किसी भी बैठक में बोलने नहीं दिया जाता और अपनी मर्जी से मनगढ़ंत प्रस्ताव पारित कर लिए जाते हैं। पात्र गरीब, वृद्धों और विधवा महिलाओं का हक मारकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 6 पात्र हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है।

मंत्रियों से मेरी पहचान, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता!

ग्रामीणों ने आवेदन में आरोप लगाया है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार का विरोध करता है, तो सचिव मुकेश तिवारी धौंस देते हुए कहता है कि मेरे रिश्तेदार जिला अध्यक्ष हैं, भोपाल मंत्रालय में मेरी मौसी का लडक़ा बैठता है और उप मुख्यमंत्री/मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल मेरे भाई के दोस्त हैं। मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सचिव की इस गीदड़ भभकी और ऊंचे राजनीतिक रसूख के डर से पूरा ग्रामवासी दहशत के साए में जीने को मजबूर है। ददराटोला पंचायत में जारी यह भ्रष्टाचार कोई अकेला मामला नहीं, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है।

दबंग पर हत्या का आरोप, पुलिस और चिकित्सा तंत्र पर उठे गंभीर सवाल

शहडोल। जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र में बाहुबल, धनबल और पुलिस-चिकित्सा तंत्र की संदिग्ध साठगांठ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दबंग रसूखदार द्वारा दिव्यांग ऑटो चालक की सरेराह बेरहमी से पिटाई किए जाने और इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत के बाद पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। मृतक के लाचार और असहाय माता-पिता ने शहडोल पुलिस अधीक्षक (एसपी) की चौखट पर दस्तक देकर गोहपारू पुलिस की कार्यप्रणाली पर लीपापोती करने तथा आरोपी को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
ग्राम गोहपारू निवासी कमला प्रसाद यादव उम्र 46 वर्ष और उनकी पत्नी सुमित्रा यादव ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में बताया कि उनका मृतक दिव्यांग पुत्र महेन्द्र यादव ऑटो चलाकर परिवार का जीवन यापन करता था। 4 जून 2026 की रात लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच महेन्द्र अपना ऑटो लेकर गोहपारू बाजार की ओर जा रहा था। शराब भट्टी के पास पहले से मदिरापान कर रहे क्षेत्र के बाहुबली व आपराधिक प्रवृत्ति के दबंग शिवम सोनी पिता छंगू सोनी ने उसे आवाज देकर जबरन रोका।
आरोप के अनुसार, पीड़ित दिव्यांग महेन्द्र ने पूर्व में आरोपी शिवम सोनी को 2 लाख रुपये कर्ज स्वरूप दिए थे। बार-बार पैसे वापस मांगने और बाजार में बेइज्जती महसूस होने की रंजिश में आरोपी आगबबूला हो गया। आरोपी ने सरेराह गालियां देते हुए दिव्यांग युवक को लात-घूंसों व चप्पलों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस बर्बरता में युवक के पेट और चेहरे पर गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों राकेश सोनी और शिवम गुप्ता ने किसी तरह बीच-बचाव कर महेन्द्र को बचाया। भागते-भागते भी आरोपी ने धमकी दी कि अगर दोबारा पैसे मांगे या किसी को बताया, तो जान से खत्म कर दूंगा।
घटना के बाद भयभीत महेन्द्र घर लौट आया और डर के मारे चुपचाप सो गया। मध्यरात्रि लगभग 01 बजे जब उसके कराहने की आवाज आई, तो उसने परिजनों को पूरी आपबीती बताई और पेट में असहनीय दर्द व उलझन की शिकायत की। अगले दिन अत्यधिक हालत बिगडऩे पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 जून की रात 08 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का सीधा आरोप है कि आरोपी के प्रभाव में आकर चिकित्सकों ने शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट में भी हेरफेर और लीपापोती की है।
मृतक के पिता का आरोप है कि गोहपारू पुलिस शुरू से ही आरोपी शिवम सोनी को संरक्षण दे रही है। घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, जिसे परिजनों ने स्वयं पेनड्राइव में सुरक्षित कर पुलिस को सौंपा। आरोप है कि थाना प्रभारी ने पेनड्राइव देखने तक से इनकार कर दिया और रोते-बिलखते गरीब माता-पिता को थाने से यह कहकर भगा दिया कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम्हें जहां शिकायत करनी है कर लो। बेखौफ आरोपी अब परिजनों को धमकी दे रहा है कि अस्पताल और पुलिस को मैंने खरीद लिया है, अगर ज्यादा उछलकूद की तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। गरीब व असहाय परिवार का इकलौता सहारा छीन चुका है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस खुली गुंडागर्दी पर क्या रुख अपनाता है या मामला ठंडे बस्ते में ही दबा रह जाता है।

राजस्व कार्यालयों की सुस्ती का खूनी परिणाम

मामूली जमीनी विवादों से गांवों में बन रहे रणक्षेत्र

शहडोल। राजस्व न्यायालयों और कार्यालयों में लंबित मामलों के प्रति प्रशासनिक उदासीनता और लेटलतीफी अक्सर आम नागरिकों को इस हद तक निराश कर देती है कि मामूली भूमि विवाद और सीमांकन के मुद्दे हिंसक और खूनी संघर्षों में बदल जाते हैं। फाइलों के निस्तारण में देरी के कारण गांवों और बस्तियों में खेत और अदालत की दहलीजें रणक्षेत्र बन रही हैं।
राजस्व प्रकरणों की उदासीनता में किसी एक तहसील मुख्यालय की बात करना बेमानी होगी। जिले की समस्त तहसील मुख्यालयों में वर्षों से चल रहे राजस्व प्रकरणों में आज भी पीड़ित न्यायालय के चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। खुद की जमीन को लेकर किसान कितने बेबस नजऱ आते हैं, यह लगभग हर सुनवाई के दौरान न्यायालय में सहजता से देखे जा सकते हैं।
वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद में जब कोई ठोस निर्णय नहीं आता ऐसी स्थिति में जमीनी विवाद के कई मामले खूनी संघर्ष में बदल जाते है। कई मामलों में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। राजस्व मामलों में अंतिम निर्णय के इंतजार में न जाने कितने लोगों की आंखें धुंधला चुकी हैं। जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे प्रकरण हैं, जिनके लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी निपटारे नहीं हो सके हैं। ऐसे में आप राजस्व विभाग के जिम्मेदार अफसरों की संवेदनशीलता का अनुमान लगा सकते हैं। जिले में सैकड़ों प्रकरणों में बुजुर्गों को सुनवाई के दौरान न्यायालय के चक्कर लगाते देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अफसर अपने मां-बाप को ऐसे ही भटकते देख सकते हैं। क्या बुजुर्गों में अपने मां-बाप की छवि नहीं देख पा रहे जिम्मेदार। वास्तव में इस समाचार का उद्देश्य जिम्मेदार अफसरों के अंतर्मन को जगाने का छोटा सा प्रयास है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में इसका फर्क़ जिम्मेदार अफसरों पर पड़ेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

नशे को कहें न, स्वस्थ्य जीवन को कहें हॉ: पुलिस अधीक्षक

मानव श्रृंखला बनाकर दिया गया नशा मुक्ति का संदेश

शहडोल। सर्तक रहें, जागरूक रहें, स्वस्थ्य रहें। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल में नशा मुक्ति का संदेश देने एवं नशे के दुष्परिणामो के प्रति समाज को जागरूक करने के उददेश्य से मानव श्रृंखला बनाई गई। पुलिस अधीक्षक ने मानव श्रृंखला में सहभागी विद्यार्थियो को सम्बोंधित करते हुए कहा कि नशा समाज को अंदर ही अंदर खोखला करता है, नशे से होने वाले दुष्परिणामो के प्रति खुद जागरूक रहे एवं अपने दोस्तो, घर परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशे को न कहें और स्वस्थ्य जीवन को हॉ कहें। उन्होंने कहा कि नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का हिस्सा बनें और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि शहडोल जिले के विभिन्न थानांतर्गत नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान प्रगति पर है। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले में नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, चैपाल इत्यादि जागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन कर नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है।

प्रशासनिक सुस्ती पर बिफरीं कमिश्नर और कलेक्टर

जनसुनवाई में उमड़ा शिकायतों का सैलाब, अधिकारियों को दी चेतावनी

शहडोल। प्रशासनिक अमले की लापरवाही और जमीनी स्तर पर जारी मनमानी की कलई एक बार फिर साप्ताहिक जनसुनवाई में खुल गई। कलेक्ट्रेट और संभागायुक्त कार्यालय में मंगलवार को दूर-दराज के गांवों से पहुंचे पीड़ितों ने अपनी-अपनी आपबीती सुनाई, तो अफसरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागायुक्त सुरभि गुप्ता और कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने मातहत अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और सभी लंबित शिकायतों का समय-सीमा के भीतर कड़ा निपटारा करने का अल्टीमेटम थमाया।

सीमांकन में अड़ंगेबाज़ी पर हडक़ंप

संभागायुक्त कार्यालय में उस वक्त स्थिति असहज हो गई जब उमरिया के मझगवां निवासी फूल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली का खुलासा किया। पीड़ित के मुताबिक वर्ष 2011-12 से कागजों में तीन किस्तों का भुगतान दर्ज होने के बावजूद उसे फूटी कौड़ी नहीं मिली। कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने इसे बेहद संगीन मामला मानते हुए एसडीएम व सीईओ पाली को तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं, बरदौहा (गोहपारू) के पीड़ित विश्वनाथ बैगा ने लोक सेवा केंद्र में महीनों पहले आवेदन के बावजूद जमीन का सीमांकन न होने का दर्द बयां किया, जिस पर एसडीएम जयसिंहनगर को घेरा गया। इसके अलावा, पाली के बकेली निवासी शांति प्रजापति ने आवास निर्माण के लिए भूमि न मिलने और पारिवारिक विवाद का मामला उठाया, जिस पर त्वरित जांच बैठा दी गई है। राशन, आयुष्मान और पेंशन के लिए भटक रहे ग्रामीण
उधर, सोन सभागार में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के समक्ष फरियादियों की लंबी कतार लगी रही। अमलाई निवासी संजना पनिका ने जाति प्रमाण पत्र और सुनीता यादव ने राशन व आयुष्मान कार्ड न बनने की गुहार लगाई। वहीं, गोहपारू के राजेश कुमार ने अर्जित अवकाश के बकाया भुगतान और रवि कुमार द्विवेदी ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने स्पष्ट लहजे में कहा कि जनता को बार-बार चक्कर कटवाने वाले जिम्मेदार अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कमिश्नर व कलेक्टर दोनों ने दोटूक निर्देश दिए हैं कि फाइलें दबाकर बैठने का ढर्रा अब नहीं चलेगा। गुणवत्ताहीन और टालमटोल वाली जांच रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों पर अब सीधी गाज गिरना तय है।

खबर संक्षेप

आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चों ने किया प्राथमिक शाला का एक्सपोजर विजिट

कोतमा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यालयी वातावरण से जोड़ने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 7 के बच्चों का शासकीय प्राथमिक शाला बनियाटोला में एक्सपोजर विजिट कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी संजीदा भगत (महिला एवं बाल विकास विभाग, अनूपपुर) तथा परियोजना अधिकारी सतीश कुमार जैन के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान बच्चों को विद्यालय के कक्षाओं, परिसर, खेल मैदान एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से परिचित कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक तथा विद्यालय की शिक्षिका ने बच्चों को सरल, रोचक और मनोरंजक तरीके से स्कूल के वातावरण, दैनिक गतिविधियों और पढ़ाई की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से बच्चों के लिए खेल-आधारित एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य बच्चों में विद्यालय के प्रति आत्मीयता विकसित करना, उनके मन से स्कूल का संकोच दूर करना तथा भविष्य में प्राथमिक शिक्षा में सहज प्रवेश सुनिश्चित करना है। इससे बच्चों का मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास भी बेहतर होता है। कार्यक्रम के दौरान परियोजना अधिकारी सतीश कुमार जैन, पर्यवेक्षक श्रीमती चिन्ती चौकसे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोरमा गुप्ता, आंगनबाड़ी सहायिका समिया बानो तथा शासकीय प्राथमिक शाला बनियाटोला वार्ड-7 की शिक्षिका सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए इस पहल को उनके उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

फलदार पौधों का पौधारोपण

कोतमा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जिला अनूपपुर के विकासखंड कोतमा अंतर्गत सेक्टर क्रमांक-4 की नवांकुर संस्था जी.एस. हितकारिणी समिति द्वारा स्वैच्छिकता पर्व के तहत ग्राम कटकोना एवं पैरीचुआ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत फलदार पौधों का पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना और ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान आम, अमरूद, आंवला, नींबू सहित विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों, युवाओं एवं प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण करते हुए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओंकार सिंह ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल पौधे लगाने का अभियान नहीं, बल्कि मातृत्व के सम्मान और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सकता है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति गठित

उमरिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माय भारत की दो स्तरीय जिला समितियों के गठन को स्वीकृति दी गई है जिसमें माय भारत जिला सलाहकार समिति एवं माय भारत जिला समन्वय समिति शामिल है। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में माय भारत जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, सीएमएचओ डा व्ही एस चंदेल , लीड बैंक मैनेजर, जनरल मैनेजर जिला उद्योग केंद्र, जिला खेल एवु युवा कल्याण अधिकारी , जनसंपर्क अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग , सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, नोडल अधिकारी एन एस एस, एन सीसी, भारत स्काउट, गाइडस, हिंदुस्तान स्काउट, गाइडस, सचिव भारत रेड क्रास सोसायटी, नोडल अधिकारी कौशल विकास विभाग , जिला रोजगार अधिकारी,विशिष्ट योग्यता अर्जित युवा सीईओ माय भारत व्दारा नामित, विशिष्ट व्यक्ति युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री व्दारा नामित तथा डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव सदस्य होगे। समिति में जिला युवा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है।

एनटीए पर फूटा गुस्सा: नीट परिणाम में 212 अंकों का बड़ा घपला!

पीड़िता ने ओएमआर शीट और पुनर्मूल्यांकन की उठाई मांग

शहडोल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा 2026 के परिणामों को लेकर एक बार फिर बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करते हुए पीड़ित छात्रा पारुल यादव ने परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। छात्रा का स्पष्ट कहना है कि उत्तर कुंजी से मिलान के बाद उसके जो अंक आ रहे थे, अंतिम परिणाम में उसमें भारी कटौती कर दी गई है। इस गंभीर विसंगति से आक्रोशित पीड़िता ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से तुरंत उत्तर पुस्तिका (ओएमआर शीट) की प्रति सौंपने और अंकों की दोबारा निष्पक्ष जांच करने की पुरजोर मांग की है।

उत्तर कुंजी का गणित सही, तो अंतिम परिणाम में यह हेरफेर क्यों?

पीड़ित परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा समाप्त होते ही जब उत्तर पुस्तिका का उत्तर कुंजी से सटीकता के साथ मिलान किया गया था, तब छात्रा के लगभग 593 अंक बन रहे थे। परिजनों का दावा है कि उन्होंने बार-बार और हर संभव तरीके से उत्तरों की पड़ताल की, जिसमें हर बार 593 अंकों का आंकड़ा ही सामने आया। परंतु जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंतिम परिणाम पत्र घोषित किया, तो छात्रा और उसके परिजनों के होश उड़ गए। परिणाम पत्र में छात्रा को मात्र 381 अंक दिए गए थे। उत्तरों के मिलान और अंतिम घोषित अंक में सीधे-सीधे 212 अंकों का विशाल अंतर दिखाई दे रहा है। परिजनों ने हुंकार भरते हुए कहा कि अंकों में इतना बड़ा अंतर किसी भी सूरत में सामान्य तकनीकी चूक नहीं हो सकता। इसके पीछे स्पष्ट रूप से परिणाम तैयार करने वाली प्रणाली की बड़ी लापरवाही या कोई गहरी साजिश दिखाई देती है।

ओएमआर शीट न मिलना बढ़ा रहा संदेह

शिकायत पत्र में छात्रा ने यह भी उजागर किया है कि परीक्षा संपन्न होने के बाद वह अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका को डाउनलोड नहीं कर सकी थी। इस वजह से उसके पास अपनी मूल उत्तर पुस्तिका का कोई आधिकारिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इसी लाचारी का फायदा उठाकर एजेंसी मनमर्जी कर रही है, जिससे यह भी जांच पाना असंभव हो गया है कि एजेंसी ने छात्रा के किन उत्तरों को सही माना और किन्हें खारिज कर दिया। इसी संदेह के आधार पर छात्रा ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से अपनी मूल उत्तर पुस्तिका तत्काल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, छात्रा पारुल यादव को 720 में से केवल 381 अंक दिए गए हैं, जिससे उसका प्रतिशतक मात्र 83.82 और अखिल भारतीय स्तर पर क्रमांक 3,21,447 दर्शाया गया है। छात्रा का दावा है कि यदि निष्पक्षता से पुनः मूल्यांकन किया जाए तो उसकी योग्यता और प्राप्तांक कहीं अधिक होंगे।

मानसिक तनाव में भविष्य दांव पर, क्या जवाब देगी एजेंसी?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भेजे गए तीखे ईमेल में छात्रा ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए लिखा है कि 593 अंकों की जगह केवल 381 अंक दिया जाना उसके साथ सीधा अन्याय है। दूसरे शिकायती पत्र में पुनर्मूल्यांकन की मांग दोहराते हुए छात्रा ने सचेत किया है कि परीक्षा एजेंसी की इस भारी भूल के कारण वह गंभीर मानसिक अवसाद और तनाव से गुजर रही है। यदि समय रहते इस अन्याय का निवारण नहीं हुआ, तो उसका संपूर्ण शैक्षणिक भविष्य हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। फिलहाल छात्रा ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराकर अपनी मांग स्पष्ट कर दी है। यद्यपि एजेंसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई या भूल स्वीकार करने का पत्र सामने नहीं आया है, परंतु इस गंभीर घटनाक्रम ने परीक्षा एजेंसी की साख पर एक बार फिर बड़ा धब्बा लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि एजेंसी इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है या फिर अपनी आदतानुसार मौन साधे रहती है।

संजय गांधी ताप विद्युत गृह में अधीक्षण अभियंता की कुर्सी पर सेटिंग का खेल!

सेवाएं-1 के सबसे मलाईदार पद पर कब्जे के लिए शह-मात का खेल तेज

मंगठार में सुलग रही सियासत

वरिष्ठता और योग्यता को ठेंगा दिखाने की तैयारी से कर्मचारियों में आक्रोश

उमरिया। जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत गृह में इन दिनों बिजली उत्पादन से ज्यादा मलाईदार कुर्सियों की बंदरबांट को लेकर अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। संयंत्र की अति संवेदनशील सेवाएं-1 इकाई में अधीक्षण अभियंता (एसई) के सबसे पावरफुल पद को हथियाने के लिए सांठ-गांठ और गंदी राजनीति का नंगा नाच शुरू हो चुका है। पावर प्लांट के गलियारों से लेकर बड़े हुक्मरानों के बंगलों तक इस कुर्सी को पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आलम यह है कि परियोजना परिसर में निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाते हुए सेटिंग के दम पर ताजपोशी की गुप्त तैयारियों को लेकर जबरदस्त आक्रोश पनप रहा है।

पर्दे के पीछे राजनेताओं की परिक्रमा

खबर है कि अधीक्षण अभियंता का यह पद पावर प्लांट के संचालन, मेंटेनेंस और करोड़ों-अरबों के तकनीकी बजट के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है। यही वजह है कि इस मलाईदार कुर्सी पर काबिज होने के लिए कई दागी और महत्वाकांक्षी अधिकारी अपने-अपने आकाओं की चौखट पर माथा टेक रहे हैं। चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है कि राजनीतिक आकाओं की सिफारिश और तथाकथित वजनदार समर्थन के दम पर वरिष्ठता सूची को दरकिनार करने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। हालांकि, प्रबंधन इस पूरे खेल पर चुप्पी साधे बैठा है, जिससे दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है।

योग्य अधिकारियों का हक मारने की साजिश!

संयंत्र के निष्ठावान कर्मचारियों और अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि प्रबंधन ने राजनीतिक दबाव या सांठगांठ के आगे घुटने टेके, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कर्मचारियों ने दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि इस अति-महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापना केवल और केवल योग्यता, वरिष्ठता और सेवा नियमों के आधार पर होनी चाहिए। यदि किसी चेहते को उपकृत करने के लिए नियमों की बलि चढ़ाई गई, तो संस्थान में विवाद और असंतोष का ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिसे संभालना प्रबंधन के बस में नहीं होगा।

ऊर्जा विशेषज्ञों की दोटूक चेतावनी

तकनीकी संस्थानों की रीढ़ कहे जाने वाले पदों पर यदि अनुभवहीन और सिफारिशी चेहरों को बैठाया गया, तो इससे पावर प्लांट की कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता पर भारी चपत लगेगी। प्रबंधन की रहस्यमयी चुप्पी इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है।

पारदर्शी प्रक्रिया का ढोंग या निष्पक्ष फैसला?

अब सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और ऊर्जा विभाग की नीयत पर उठ रहा है। क्या प्रबंधन पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्यता को प्राथमिकता देगा या फिर पर्दे के पीछे चल रहे सिफारिशी खेल के आगे नतमस्तक हो जाएगा? फिलहाल पूरे मंगठार और उमरिया जिले की निगाहें भोपाल में बैठे आला अधिकारियों पर टिकी हैं। अगर समय रहते प्रक्रिया को सार्वजनिक और निष्पक्ष नहीं बनाया गया, तो यह मामला आने वाले दिनों में एक बड़े प्रशासनिक बवंडर का रूप ले सकता है।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

मदिरा दुकान के बाहर बाइक की टंकी पर टिका मिला शव

उमरिया। जिले के चंदिया नगर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के ठीक सामने सोमवार देर रात उस वक्त हडकंप मच गया, जब बाइक पर बैठे-बैठे ही एक युवक ने दम तोड़ दिया। मदिरा दुकान के मुहाने पर हुई इस अचानक और रहस्यमयी मौत से पूरे इलाके में सन्नाटा पसार गया है। हैरत की बात यह रही कि बारिश के बीच बाइक की टंकी पर सिर रखे युवक को लोग काफी देर तक सोता हुआ समझते रहे, लेकिन जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, तब जाकर मौत का खौफनाक सच सामने आया।

बेसुध पड़ा रहा युवक, लोग समझते रहे विश्राम- प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक अपनी बाइक से अंग्रेजी शराब दुकान के पास पहुंचा था। गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने बड़े सामान्य तरीके से अपना हेलमेट उतारा और बाइक पर टांग दिया। कुछ देर तक वह यूं ही बैठा रहा, फिर अचानक उसने बाइक की ईंधन टंकी पर अपना सिर टिका लिया। आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों को लगा कि युवक थका-मांदा है और कुछ देर सुस्ता रहा है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मगर इसके बावजूद युवक के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। पानी में पूरी तरह भीगने के बाद भी जब वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, तब वहां मौजूद लोगों का माथा ठनका। शंका होने पर स्थानीय निवासियों ने पास जाकर देखा और फिर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी।

पुलिस जांच में खुली शिनाख्त- सूचना मिलते ही चंदिया थाना पुलिस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब युवक को संभाला तो उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने जब युवक के सामान और पहचान पत्रों की तलाशी ली, तो उसकी पहचान शिवकुमार बैगा उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम झाला थाना चंदिया के रूप में हुई। मृतक का गांव घटनास्थल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। मृतक की बाइक पर कुछ सामान भी बंधा हुआ था, जिसे बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढका गया था। घटना की भनक लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

पीएम रिपोर्ट पर टिकी नजरें- अंग्रेजी शराब दुकान जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके के सामने हुई इस संदिग्ध मौत ने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय व्यवस्था पर भी कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या युवक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हुआ, उसे साइलेंट अटैक आया या फिर मदिरा दुकान के आसपास किसी तरह की जहरीली वस्तु/पदार्थ का सेवन इसकी वजह बनी? रात के वक्त अपने गांव से इतनी दूर शराब दुकान के पास पहुंचने के पीछे का क्या कारण था? पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया

पसान नगर परिषद को मिला नया जनप्रतिनिधि नेतृत्व

मध्य प्रदेश शासन ने 6 पार्षदों को किया मनोनीत, नगर विकास को मिलेगी नई गति

हरिभूमि न्यूज बदरा/जमुना। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद पसान में छह पार्षदों का मनोनयन किया गया है। शासन के इस निर्णय के बाद नगर परिषद में जनप्रतिनिधित्व और अधिक सशक्त होगा तथा नगर के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मनोनीत पार्षदों ने शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नगरहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद पसान में अनुमय सिंह (वार्ड 9), जनमेजय दुबे (वार्ड 17), दिलीप झा (वार्ड 2), अजय द्विवेदी (वार्ड 18), यादवेंद्र सिंह (वार्ड 3) एवं उदय प्रताप सिंह (वार्ड 1) को पार्षद के रूप में मनोनीत किया गया है। नवनियुक्त पार्षदों ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करेंगे। नगर में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए परिषद और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नगरवासियों ने भी शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नए मनोनीत पार्षद नगर के सर्वांगीण विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सभी नवनियुक्त पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। मध्य प्रदेश शासन के इस मनोनयन के बाद नगर पालिका परिषद पसान में विकास कार्यों को और गति मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नागरिकों का मानना है कि नए पार्षद जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए नगर के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

हाई स्कूल में फैली बदहाली, परिसर बना गोबर और गंदगी का टापू

सेमरा के शासकीय एकीकृत हाई स्कूल की दुर्दशा

गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र; जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज, कोतमा। विकासखंड अनूपपुर के ग्राम सेमरा स्थित शासकीय एकीकृत हाई स्कूल से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नव-निर्मित विद्यालय परिसर इन दिनों गोबर, कीचड़ और गंदगी से इस कदर पट गया है कि बच्चों के लिए स्कूल परिसर में चलना तक मुश्किल हो गया है। परिसर की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो विद्यालय नहीं, बल्कि मवेशियों का बाड़ा हो। प्राप्त वीडियो और तस्वीरों में विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार, सीढ़ियों, बरामदों और आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गोबर फैला हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के पानी के कारण यह गंदगी पूरे परिसर में फैल गई है, जिससे दुर्गंध के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी के बाद परिसर को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण मवेशी रातभर वहीं डेरा डालते हैं और सुबह तक पूरा परिसर गंदगी से भर जाता है। विद्यालय की साफ-सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिसर में नियमित सफाई नहीं होने के कारण स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। आरोप है कि विद्यालय के प्राचार्य एवं कुछ स्टाफ के समय पर उपस्थित नहीं रहने से परिसर की निगरानी और रखरखाव पूरी तरह भगवान भरोसे है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि छात्र-छात्राएं इसी गंदगी और बदबू के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। गोबर, जलभराव और मच्छरों की बढ़ती संख्या के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि इस तरह का वातावरण बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विद्यालय परिसर में सरकार द्वारा खेलकूद और ओपन जिम के उपकरण तो लगाए गए हैं, लेकिन उनके आसपास भी गंदगी और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे सरकारी संसाधनों के रखरखाव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से मामले का तत्काल संज्ञान लेकर विद्यालय परिसर की साफ-सफाई सुनिश्चित कराने, मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगाने तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावों को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

अमृत हरित महाअभियान आज अमरकंटक में: 5,171 पौधों का होगा वृहद वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जनभागीदारी से हरित होगा अमरकंटक

अमरकंटक। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार आज 22 जुलाई को नगर परिषद अमरकंटक द्वारा अमृत हरित महाअभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत नगर परिषद अमरकंटक को 5,171 पौधे रोपित करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे जनसहभागिता के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र का विस्तार, जलवायु संतुलन बनाए रखना तथा लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया जाएगा, ताकि अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर हरियाली बढ़ाने का स्थायी प्रयास बन सके। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों, शासकीय कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नगर परिषद का प्रयास है कि यह अभियान जन-आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करे और प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। नगर परिषद अमरकंटक की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती सिंह उईके, उपाध्यक्ष रज्जू सिंह नेताम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी चैन सिंह परस्ते सहित सभी पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों ने नगरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़ें। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प ले, जिससे अमरकंटक को और अधिक हरित, स्वच्छ एवं पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सके।

खबर संक्षेप

जिले में गत 24 घंटे में 35.2 मिमी वर्षा दर्ज

उमरिया। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि गत 24 घंटे में 35.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बांधवगढ़ तहसील में 50.2 मिमी, मानपुर तहसील में 32.8 मिमी, पाली तहसील में 43.8 मिमी, नौरोजाबाद तहसील में 41.2 मिमी, चंदिया में 22.2 मिमी, करकेली तहसील में 37.8 मिमी, बिलासपुर तहसील में 18.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
जिले में 1 जून से लेकर 21 जुलाई तक 321.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 442.8 मिमी, मानपुर तहसील में 195.9 मिमी, पाली तहसील में 367.6 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 353.4 मिमी, चंदिया तहसील में 234.5 मिमी, करकेली तहसील में 396.9 मिमी, बिलासपुर तहसील में 262.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक 681.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 615.3 मिमी, मानपुर तहसील में 694 मिमी, पाली तहसील में 627.5 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 609.2 मिमी, चंदिया तहसील में 798.7 मिमी, करकेली तहसील में 616.5 मिमी, बिलासपुर तहसील में 801.2 मिमी वर्षा शामिल है।

सड़क हादसे में महिला की मौत, दो अन्य हुये घायल

कटनी। एन.के.जे. थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुहला में हुये हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गोपाल नगर की रहने वाली 45 वर्षीय हिमांशी परमानी अपने वाहन से जा रही थीं, तभी तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक GJ 31 U 0245 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हिमांशी परमानी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह बरही थाना क्षेत्र में हुये दो अलग-अलग हादसों में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। जानकारी के अनुसार हनुमान मंदिर मेन रोड इटौरा के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए इटौरा निवासी 25 वर्षीय सुमित तिवारी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुमित को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरी घटना करौंदी कला पुलिया के पास मेन रोड पर हुई। यहाँ बोलेरो क्रमांक MP 21 ZC 5143 के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए नयागांव लखेरा निवासी 44 वर्षीय अरविंद सोनी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। बरही पुलिस ने दोनों मामलों में धारा 281 और 125ए बी.एन.एस. के तहत एफआईआर दर्ज की है।

बाइक सवारों से चाकू की नोंक पर की गई लूटपाट

कटनी। कुठला थाना क्षेत्र अंतर्गत चाका रोड पर देर रात चाकू की नोक पर लूटपाट की एक वारदात हुई। बाइक सवार युवकों को घेरकर तीन बदमाशों ने चाकू अड़ा दिया और जान से मारने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सुडौर, थाना शाहनगर का रहने वाला 20 वर्षीय दुर्गेश चौधरी रविवार रात करीब 8 बजे अपने साथियों के साथ चाका रोड से गुजर रहा था तभी शिवम ढाबा से कुछ दूरी पहले घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाते, आरोपी आकाश कोल और उसके साथ मौजूद दो अन्य लड़कों ने पीड़ित पर चाकू अड़ा दिया। आरोपियों ने चाकू की नोंक पर युवकों को कब्जे में ले लिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने सरेराह युवकों के साथ लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद सहमे पीड़ित ने तत्काल कुठला थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर नामजद आरोपी आकाश कोल और उसके दो अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस हुलिए के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश के लिए प्रयास कर रही है।

कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के दिए निर्देश

जनसुनवाई में सुनी गई 116 आवेदकों की समस्याएं

उमरिया। साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने जिले के दूर दराज से आए 116 आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा आवेदनों के निराकरण के लिए आवेदन संबंधित विभाग की ओर प्रेषित किया तथा विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करनें के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में राज कुमारी त्रिपाठी पति स्व. ओमकार प्रसाद त्रिपाठी निवासी कंचनपुर थाना नौरोजाबाद ने पुत्र विवेक त्रिपाठी व्दारा भरण पोषण दिलाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम बांधवगढ़ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रामदयाल विश्वकर्मा सेवा निवृत्त हेल्पर डब्ल्यू आर डी ने डी पी एफ विभागीय भविष्य निधि का भुगतान एवं पेंशन चालू कराने, बालगोविंद सिंह ग्राम तेंदुहा ने वृध्दावस्था , दिव्यांग पेंशन दिलाने, संतोषी कुशवाहा मोहनपुरी ने शासकीय हाई स्कूल खलेसर ने मध्यान्ह भोजन के रसोइया पद मे रखें जाने, राम बाई ग्राम पंचायत नरवार 29 ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने, दउवाराम सिंह ग्राम करकटी ने वृक्षारोपण कार्य चौकीदार का मानदेय दिलाने, कैलाश संत पनिका ग्राम करकेली ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, राम कुमार बैगा ग्राम सलैया ने फौती नामांतरण कराने, चंद्रशेखर रजक, कपिल रजक, सुनीता रजक, सरोज रजक अमरपुर ने मजदूरी का भुगतान कराने, कल्लू यादव धनवाही ने पुस्तैनी जमीन पर ग्राम पंचायत व्दारा सामुदायिक भवन बनाने, पवन कुमार गुप्ता ग्राम धनगी ने पीएम किसान सम्मान निधि की समस्यां से निजात दिलाने संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करनें के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, प्रत्युष श्रीवास्तव, तहसीलदार बांधवगढ़ दिलीप सोनी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

शासकीय कन्या विद्यालय पाली के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य की कथित राजनीतिक गतिविधियों की निष्पक्ष जांच की मांग

पाली। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने शासकीय कन्या विद्यालय पाली के प्राचार्य रामशरण द्विवेदी एवं उप प्राचार्य ममिता विलखरे सहित कुछ शिक्षकों की कथित राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिरसिंहपुर पाली को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हर्ष अवधिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो एवं अन्य जानकारियों में शासकीय कन्या विद्यालय पाली के प्राचार्य रामशरण द्विवेदी एवं उप प्राचार्य ममिता विलखरे कथित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। यदि जांच में यह तथ्य सही पाए जाते हैं कि उन्होंने शासकीय पद पर रहते हुए किसी राजनीतिक या राजनीतिक रूप से संबद्ध छात्र संगठन की गतिविधियों में भाग लिया, तो यह शासकीय सेवा आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं शिक्षकों से पूर्ण निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। यदि विद्यालय के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य स्वयं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते पाए जाते हैं, तो इससे शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता, विद्यार्थियों का विश्वास तथा शासकीय सेवा की गरिमा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, कार्यक्रम में प्राचार्य रामशरण द्विवेदी, उप प्राचार्य ममिता विलखरे एवं अन्य संबंधित शिक्षकों की भूमिका की जांच की जाए तथा यदि सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन सिद्ध होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। प्रदेश सचिव हर्ष अवधिया ने कहा कि सरकारी विद्यालय किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार का मंच नहीं हैं। यदि कोई शासकीय अधिकारी या शिक्षक अपने पद की गरिमा को छोड़कर राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए और दोषी पाए जाने पर किसी को भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से हर्ष अवधिया, दुर्गेश नामदेव, जावेद खान, रवि प्रजापति, फैजान नियाजी एवं लकी वर्मा सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पावर हाउस में ऊंचाई से गिरकर श्रमिक घायल

अमलाई। ओरिएंट पेपर मिल्स (ओपीएम) के पावरहाउस प्लांट में सोमवार को ऊंचाई से गिरने के कारण एक श्रमिक घायल हो गया। घटना के बाद श्रमिकों में नाराजगी है और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पावरहाउस में कार्यरत राम चरण साहू से ऊंचाई पर पाइपलाइन में कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान श्रमिक को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल श्रमिक को प्राथमिक उपचार के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। श्रमिकों का आरोप है कि ऊंचाई पर कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ रही है। घटना के बाद कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता, तो इस प्रकार की दुर्घटना टाली जा सकती थी।

पेपर लीक के खिलाफ एवं सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध मार्च

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

आम आदमी पार्टी द्वारा देश के प्रख्यात वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक के लोकतांत्रिक संघर्ष के समर्थन तथा पेपर लीक प्रकरण में जवाबदेही तय करने एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च रेलवे स्टेशन चौराहा, कटनी से प्रारंभ होकर अहिंसा चौक तक निकाला गया। मार्च में पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई।
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष एड. अनिल सिंह सेंगर ने कहा कि, स्देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य बार-बार होने वाले पेपर लीक से बर्बाद हो रहा है। जब एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक युवाओं के हित में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, तब उनकी आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होना आवश्यक है और पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
विरोध मार्च के दौरान प्रदेश कमेटी सदस्य शिवप्रताप सिंह परमार जिलाध्यक्ष अनिल सिंह सेंगर, उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, युवा विंग जिलाध्यक्ष अंकित खटीक, प्रवक्ता संतोष सिंह, सहसचिव रामसिया गुप्ता ,करण दहिया, अंकित खरे आदि शामिल रहे।

वित्तीय धोखाधड़ी मामले में पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई: आरोपियों की गिरफ्तारी

शहडोल। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में लंबित वित्तीय अपराधों की समीक्षा करते हुए धोखाधड़ी के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निवेश के नाम पर अधिक लाभ का प्रलोभन देकर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष व प्रभावी विवेचना के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।

मामले का विवरण:

आवेदक मृगनयन सिंह (पिताः मोहन सिंह), निवासी गोपालपुर-करकटी रोड, थाना बुढार (जिला शहडोल) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (दिनांक 19.05.2026) की जांच के दौरान यह बात सामने आई। जांच में संबंधित व्यक्तियों के कथनों और दस्तावेजों के परीक्षण से प्रथम दृष्टया पाया गया कि 'GNS FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.' में निवेश के रूप में अधिक लाभ का लालच देकर लोगों से पैसे निवेश कराए गए थे। इसके बाद ग्राहकों की अनुमति के बिना उनके डिमैट खातों में ट्रेडिंग करके उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया।

थाना बुढार में अपराध दर्ज:

जांच में पर्याप्त आधार पाए जाने पर दिनांक 20.07.2026 को थाना बुढार में निम्नलिखित आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थीःसुखनंदन यादव,मुकेश यादव,सरोज यादव,मोहम्मद अमीम,विजय पाल एवं अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

समीक्षा बैठक और सख्त निर्देशः

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, डाक्टर संजय कुमार अग्रवाल शहडोल द्वारा कार्यालय में गठित जांच दल की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मामले के संबंध में बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निम्नलिखित आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए:साक्ष्य संकलनः प्रकरण से जुड़े सभी डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों को प्राथमिकता से एकत्र किया जाए।
तकनीकी साधनों (साइबर सेल/डेटा एनालिसिस) का प्रयोग कर आरोपियों की लोकेशन और गतिविधियों पर नज़र रखी जाए।
शीघ्र गिरफ्तारीः विशेष टीम बनाकर सभी नामजद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
शहडोल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के पैसों से खिलवाड़ करने वाले वित्तीय अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सुरम्य पार्क भ्रमण से नागरिकों को मिला प्रेरणा का संदेश

स्वस्थ जीवनशैली के लिये स्वच्छता को आदत बनाने किया प्रेरित

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत निगम प्रशासन द्वारा सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाकर अभियान को जन-आंदोलन के रूप में बढ़ानें के प्रयास किये जा रहे है। अभियान के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में निरंतर जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता को दैनिक आदत बनाकर स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
निगम प्रशासन के मार्गदर्शन में आईईसी टीम द्वारा अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत निगम की स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर श्रीमती नीलम जगबानी ने नागरिकों से सीधा संवाद कर नागरिकों से स्वच्छ वातावरण बनाए रखने, घर एवं आसपास नियमित साफ-सफाई अपनाने तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी। ब्रांड एंबेसडर ने वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम का काम नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
अभियान के तहत आचार्य विनोवा भावे वार्ड बड़ी खिरहनी एवं छोटी खिरहनी में शीला स्व-सहायता समूह एवं सरस्वती स्व-सहायता समूह की महिलाओं के साथ विशेष स्वच्छता संवाद आयोजित किया गया। बैठक में उपस्थित महिलाओं को अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए घर, मोहल्ले एवं सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। महिलाओं से अपील की गई कि वे स्वच्छता की अलख जगाकर जनभागीदारी के माध्यम से अभियान को सफल बनाएं।
बी.डी.अग्रवाल वार्ड के सुभाष चौक में सफाई मित्रों की विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्य शाला में स्वच्छता मित्रों को सफाई कार्य के दौरान पी.पी.ई किट का अनिवार्य उपयोग करने, कचरा उठाव एवं निपटान के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके, ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियां एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी दी जाकर बताया गया इन सावधानियों को अपनाने से सफाई मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही सफाई कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

गंदगी फैलाने एवं अमानक पॉलीथिन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना कार्यवाही

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न वार्डों में जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों, दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुले में कचरा नहीं फेंकने, अमानक पॉलीथिन का उपयोग नहीं करना तथा निर्धारित डोर-टू-डोर कचरा वाहनों में ही कचरा देने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने एवं खुले में कचरा फेंकने वालों को समझाइश के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नगर निगम की स्वच्छता टीम द्वारा स्पॉट फाइन लगाया जा रहा है।
स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने बताया कि विगत दिवस स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संत कवरराम वार्ड के माधव नगर बाजार क्षेत्र में अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों में गंदगी फैलाने वाले 10 व्यक्तियों, प्रतिष्ठान संचालकों पर दो - दो रुपये के मान से कुल दो हजार रुपये का स्पॉट फाइन किया गया। वहीं अमानक पॉलीथिन का उपयोग करते पाए जाने पर एक प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि शहर की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, कचरा निर्धारित वाहनों में ही दें तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

खबर संक्षेप

कोतमा बाजार एरिया के 294 परिवारों ने भू-अधिकार के लिए हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नगरपालिका परिषद कोतमा के बाजार एरिया स्थित नजूल भूमि पर वर्षों से निवास और व्यवसाय कर रहे 294 परिवारों ने स्थायी भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका (भूमि स्वामित्व अधिकार) की मांग को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि बाजार क्षेत्र के निवासी रीवा रियासत के महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 लागू होने से पहले से इस भूमि पर काबिज हैं। उनका कहना है कि वर्ष 1946-47 में इस क्षेत्र की व्यवस्थित प्लॉटिंग कर बाजार बसाया गया था और तब से लोग अपने मकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाकर लगातार रह रहे हैं। याचिका के अनुसार वर्तमान में बाजार क्षेत्र में 294 आवासीय एवं व्यावसायिक भवन स्थित हैं। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि नजूल के रूप में दर्ज है, जबकि नागरिक लंबे समय से यहां रहकर नगरपालिका को कर एवं अन्य शुल्क भी अदा करते रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आज तक भूमि का स्वामित्व अधिकार नहीं मिल सका है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें केवल लीज पर भूमि देने के बजाय स्थायी भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदान कर मालिकाना हक दिया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मामले में जमाना अहमद सिद्दीकी सहित बाजार क्षेत्र के कई नागरिक याचिकाकर्ता हैं। उच्च न्यायालय ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया है। अब स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्षों पुरानी भू-अधिकार की मांग का समाधान निकल सकेगा।

स्कूल के सामने तेज रफ्तार वाहनों पर लगे लगाम

अमरकंटक। नगर परिषद अमरकंटक क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है। कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन विद्यालय एवं शिशु मंदिर के सामने से गुजरने वाले मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार से बढ़ रहे दुर्घटना के खतरे को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि प्रकाश द्विवेदी विक्की ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपकर तत्काल स्पीड ब्रेकर निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय के सामने से होकर दोपहिया, चारपहिया और अन्य भारी वाहन तेज गति से गुजरते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिक इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और बच्चों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। सांसद प्रतिनिधि प्रकाश द्विवेदी विक्की ने नगर परिषद प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने निर्धारित मानकों के अनुरूप स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाए तथा स्कूल क्षेत्र होने की चेतावनी देने वाले संकेतक भी लगाए जाएं, ताकि वाहन चालक अपनी गति नियंत्रित रखें और संभावित हादसों से बचा जा सके। यदि समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए जनहित और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद को इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन प्राप्त होने के बाद सीएमओ से इस मांग पर त्वरित एवं सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। वहीं स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर बनने से बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

करोड़ों का कोयला, बदहाल सड़क, बदरा-कुशियारा मार्ग बना मौत का रास्ता देश को रोशन करने वाले कोयलांचल की बदहाली ने खोली विकास की पोल

पहली ही बारिश में ध्वस्त हुई सड़क; रोज हो रहे हादसे जिम्मेदार विभाग मौन, ग्रामीणों ने दी जनआंदोलन की चेतावनी

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। देश के कई राज्यों को बिजली उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध कराने वाला अनूपपुर जिले का जमुना-कोतमा कोयलांचल आज अपनी ही बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। अरबों रुपये के कोयला उत्पादन और करोड़ों रुपये के राजस्व देने वाले इस क्षेत्र की तस्वीर विकास के सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही है। एसईसीएल जमुना-कोतमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बदरा-कुशियारा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पहली ही बारिश में पूरी तरह बदहाल होकर दलदल, गहरे गड्ढों और जलभराव में तब्दील हो गया है। सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ग्रामीण इसे अब सड़क नहीं, मौत का रास्ता कहने लगे हैं। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों को यह तक समझ नहीं आता कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां। प्रतिदिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर घायल हो रहे हैं। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। कई बार एम्बुलेंस भी इस सड़क पर धीमी गति से चलने को मजबूर हो जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर भी खतरा मंडराता है। विडंबना यह है कि इसी मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों भारी वाहन कोयला, राखड़ और औद्योगिक सामग्री लेकर गुजरते हैं। इसी क्षेत्र से निकलने वाला कोयला देश के बड़े बिजलीघरों तक पहुंचता है और सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है, लेकिन जिस सड़क से यह राष्ट्रीय संपदा बाहर जाती है, उसी सड़क की मरम्मत के लिए वर्षों से कोई ठोस योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति दिया तले अंधेरा की कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है।

ग्रामीणों के अनुसार एसईसीएल और मोजर बेयर विद्युत उत्पादन कंपनी, जैतहरी के बीच हुए समझौते के बाद राखड़ से भरे भारी-भरकम हाईवा वाहनों की लगातार आवाजाही ने सड़क की हालत पूरी तरह बिगाड़ दी। ओवरलोड वाहनों के लगातार दबाव से सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई और अब बारिश ने इसे पूरी तरह जर्जर बना दिया है। कई स्थानों पर डामर पूरी तरह खत्म हो चुका है और सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में बदल गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की इस बदहाली की जानकारी कई बार एसईसीएल प्रबंधन, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिले। मरम्मत के नाम पर कहीं-कहीं खानापूर्ति की गई, जो पहली बारिश में ही बह गई। नतीजा यह है कि हजारों की आबादी रोजाना इस जानलेवा सड़क से गुजरने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने से केवल आवागमन ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और कृषि पर भी पड़ रहा है। किसान समय पर अपनी उपज मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। स्कूली बच्चे बारिश के दिनों में कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। छोटे व्यापारी और दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाने में देरी होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि चुनाव के समय विकास, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह क्षेत्र नेताओं और जिम्मेदार विभागों की प्राथमिकता से बाहर हो जाता है। करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाले इस कोयलांचल के लोगों को आज भी अच्छी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले भारी वाहनों के संचालन की जवाबदेही तय की जाए। जिन कंपनियों के वाहनों से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, उनसे सड़क निर्माण और मरम्मत की लागत वसूली जाए तथा भविष्य में ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ ही सड़क के दोनों ओर मजबूत जलनिकासी व्यवस्था विकसित की जाए ताकि हर बारिश में यही स्थिति दोबारा न बने। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही बदरा-कुशियारा मार्ग का स्थायी निर्माण, चौड़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण मरम्मत शुरू नहीं हुई तो क्षेत्रवासी व्यापक जनआंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन, चक्काजाम और प्रशासनिक कार्यालयों का घेराव भी किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, एसईसीएल, लोक निर्माण विभाग और संबंधित जनप्रतिनिधियों की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह क्षेत्र देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तब क्या यहां के लोगों को सुरक्षित सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिलनी चाहिए? क्या करोड़ों रुपये का राजस्व देने वाले इस कोयलांचल के हिस्से में केवल धूल, गड्ढे, कीचड़ और उपेक्षा ही आएगी, या फिर जिम्मेदार विभाग इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे? यही सवाल आज बदरा-कुशियारा के हजारों ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं।

50 चालान, 1.32 लाख से अधिक का जुर्माना, नियम तोड़ने वालों में मचा हड़कंप

स्कूली वाहनों पर यातायात पुलिस का 'ऑपरेशन सेफ्टी'

नाबालिग चालकों, ड्रिंक एंड ड्राइव और बिना परमिट वाहनों पर सख्त कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब (आईपीएस) के निर्देशन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात पुलिस अनूपपुर द्वारा जिलेभर में स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कई स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने, शराब के नशे में वाहन संचालन और बिना आवश्यक दस्तावेज के वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि 20 जुलाई एवं 21 जुलाई को चलाए गए अभियान में कुल 50 चालान बनाए गए। इनमें 20 जुलाई को 17 चालानों पर 66,000 तथा 21 जुलाई को 33 चालानों पर 66,600 का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। इस प्रकार कुल 1,32,600 का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान 12 नाबालिग वाहन चालक वाहन चलाते पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी 3 अन्य नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जिससे नाबालिगों की कुल संख्या 12 हो गई। इसके अलावा 5 कमर्शियल वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए, जिनके वाहन जब्त कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं 13 मामलों में परमिट शर्तों का उल्लंघन, 2 वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, 1 चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा 1 वाहन बिना बीमा संचालित मिलता पाया गया, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने सभी स्कूल वाहन संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना फिटनेस, बिना आवश्यक सुरक्षा उपकरण, बिना वैध दस्तावेज अथवा नियमों के विपरीत संचालित होने वाले स्कूल वाहनों के विरुद्ध आगे भी लगातार विशेष जांच अभियान जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश शासन ने अनूपपुर नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों की सूची की घोषित

हरिभूमि न्यूज<अनूपपुर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिका परिषद अनूपपुर के लिए मनोनीत पार्षदों की घोषणा कर दी गई है। शासन के आदेश के अनुसार नगर विकास एवं जनप्रतिनिधित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से छह सदस्यों को मनोनीत पार्षद बनाया गया है। यह नियुक्तियां मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई हैं। घोषित सूची के अनुसार मनोनीत पार्षदों में मनोज दुबे, नीता प्रजापति, पंकज अग्रवाल, दिन दयाल राठौर, बुद्धसेन पटेल तथा आदित्य प्रताप सिंह को शामिल किया गया है। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति के बाद स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने सभी नवनियुक्त पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया है कि वे नगर के सर्वांगीण विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। लोगों का मानना है कि परिषद में नए सदस्यों के जुड़ने से विकास कार्यों की निगरानी और जनसमस्याओं के समाधान में भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा। नगर पालिका परिषद अनूपपुर में मनोनीत पार्षदों के शामिल होने से परिषद की कार्यप्रणाली को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही नगर के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित के निर्णयों में इन पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने भी आशा जताई है कि नवनियुक्त पार्षद शासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए नगर के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं 42 आवेदकों की समस्याएं, समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने 42 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसमें प्राप्त होने वाले आवेदनों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता तथा प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी, अपर कलेक्टर बलवीर रमन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर प्राशी अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में नगर परिषद बरगवां-अमलाई निवासी रुकमणी महरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम औढ़ेरा निवासी संजय जड़िया ने नक्शा तरमीम कराने, ग्राम कदमटोला निवासी रामप्रसाद ने अपने पुत्र का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने, बिजुरी निवासी नारायण महरा ने भूमि सीमांकन कराने तथा वेंकटनगर निवासी सुभद्रा द्विवेदी ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ग्राम मेडियारास निवासी परसादी चर्मकार ने अपने पुत्र के उपचार के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने, पोड़ी मानपुर निवासी मनोज माझी ने जाति प्रमाण-पत्र बनवाने तथा अनूपपुर के वार्ड क्रमांक-2 निवासी मोहम्मद इल्ताफ खान ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और समाधान की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आमाडांड मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन बने हादसों की वजह राहगीरों की बढ़ी परेशानी

हरिभूमि न्यूज राजनगर। रामनगर थाना क्षेत्र के आमाडांड मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक और डंपरों के कारण यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। मार्ग पर बढ़ते भारी वाहनों के दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग से आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी के अनुसार आमाडांड कालरी के बाहर आमाडांड-बरतराई मार्ग पर दिनभर बड़ी संख्या में ट्रक और डंपर सड़क किनारे खड़े रहते हैं। रात करीब आठ बजे के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है, जब कोयला लोड करने के बाद भारी वाहन सड़क के एक हिस्से पर लंबी कतार में खड़े कर दिए जाते हैं। इससे पहले से ही संकरी सड़क पर छोटे वाहनों, चार पहिया वाहनों तथा अन्य ट्रकों का आवागमन बाधित हो जाता है और कई बार लंबा जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहनों की लंबी कतार के कारण सामने से आने वाले वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यही हाल आमाडांड से फुलकोना और सेमरा मार्ग पर भी देखने को मिलता है, जहां सड़क किनारे खड़े भारी वाहन आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। राहगीरों और वाहन चालकों का कहना है कि कई बार इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का मानना है कि मुख्य सड़क पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए तथा इनके लिए अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि यातायात सुचारु रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि आमाडांड मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़े होने वाले भारी वाहनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

पवित्र नगरी अमरकंटक में ढाई घंटे झमाझम बारिश, आषाढ़ में घने कोहरे ने बढ़ाई वादियों की खूबसूरती

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। मध्य प्रदेश की पावन नगरी एवं मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक में मंगलवार को मौसम ने ऐसा मनमोहक रूप दिखाया कि पूरा क्षेत्र प्रकृति की अद्भुत छटा से सराबोर हो गया। दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश लगातार लगभग ढाई घंटे तक होती रही, जिससे सड़कें, घाटियां और वन क्षेत्र पानी से तर-बतर हो गए। बारिश थमने के बाद शाम होते-होते घने कोहरे ने पूरे अमरकंटक को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बादल धरती पर उतर आए हों। पिछले एक सप्ताह से अमरकंटक क्षेत्र में लगातार वर्षा का दौर जारी है। कभी तेज बारिश तो कभी रिमझिम फुहारों ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। मंगलवार की झमाझम वर्षा के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और वातावरण पूरी तरह शीतल हो गया। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली तथा ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद सुहावना बना दिया। बारिश के बाद छाए घने कोहरे ने अमरकंटक की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा दिए। हरियाली से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, वन क्षेत्र और घाटियां बादलों एवं कोहरे से ढक गईं, जिससे पूरा क्षेत्र किसी हिल स्टेशन जैसा नजर आने लगा। मां नर्मदा की पावन नगरी का यह मनोरम दृश्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। कई लोगों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। हालांकि, घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। प्रशासन ने भी लोगों से वर्षा के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अमरकंटक का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, वायु गुणवत्ता सूचकांक 18 रहने से हवा अत्यंत स्वच्छ श्रेणी में रही। स्वच्छ वातावरण और ठंडी फिजाओं का लोगों ने भरपूर आनंद लिया। लगातार हो रही वर्षा से क्षेत्र के जलाशयों, नदियों और प्राकृतिक जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है, जिससे किसानों को खरीफ फसलों के लिए लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, मानसून के इस खूबसूरत मौसम ने अमरकंटक की प्राकृतिक आभा को और निखार दिया है, जिससे आने वाले दिनों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।